Schools covered under National Service Scheme

748. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minsiter of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the coverage under National Service Scheme in Schools is satisfactory;

(b) if so, the number of schools covered so far under the scheme in each State;

(c) if not, the reasons for the less coverage; and

(d) the steps contemplated in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK) : (a) to (d) The N.S.S. was initially introduced in 1969 only for the student youth of colleges and universities. The total number of N.S.S. Volunteers in the country during 1994-95 was 11,73,350. Out of this, student coverage at college and University level was 9,36,650 and the school (+ 2) level it was 2,36,700. The decision to extend N.S.S. to + 2 level schools on an experimental basis was taken only in 1985 and accordingly it was introduced in two states namely Karnataka and Tamil Nadu with limited number of volunteers. On receiving encouraging response at +2 in these two states, it was decided in 1993-94 to extend it to + 2 level schools of other States/Uts. The number of schools covered under the scheme during 1994-95 was 2971. The state-wise detail is enclosed as statement (*see* below)

The following steps have been initiated to augment N.S.S. strength in Schools :

(i) It has been decided that 75% of further increase in Volunteer Strength will be at +2 level in future.

(ii) All State Government and UT Administrations have been requested to allocate this additional N.S.S. Volunteers strength accordingly.

(iii) The matter has also been taken up with Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti to introduce N.S.S. in their schools.

Allocation of NSS Student Volunteers (Statewise) During 1994-95

Sl. No.	Name of State	Allocated strength	Allocation at +2 level	No. of Units at +2 level
1.	Andhra Pradesh	1,10,000	24,000	248
2.	Assam	18,000	—	—
3.	Arunachal Pradesh	800	—	—
4.	Bihar	47,000	—	—
5.	Gujarat	65,000	16,500	269
6.	Goa	6,000	4,500	45
7.	Haryana	45,000	15,000	150
8.	Himachal Pradesh	16,000	—	—
9.	Jammu & Kashmir	5,000	—	—
10.	Karnataka	80,000	29,000	290
11.	Kerala	65,000	2,000	20
12.	Madhya Pradesh	68,000	3,000	30
13.	Manipur	4,500	—	—
14.	Maharashtra	1,00,000	—	—
15.	Meghalaya	7,000	—	—
16.	Nagaland	2,000	—	—

Sl. No.	Name of State	Allocated strength	Allocation at +2 level	No. of Units at +2 level
17.	Mizoram	10,000	—	—
18.	Orissa	70,000	—	—
19.	Punjab	75,000	27,700	277
20.	Rajasthan	47,700	12,000	120
21.	Sikkim	3,000	—	—
22.	Tamil Nadu	1,40,000	50,000	1,000
23.	Tripura	6,000	—	—
24.	Uttar Pradesh	1,05,000	—	—
25.	West Bengal	30,000	15,800	158
26.	Andaman & Nicobar	250	—	—
27.	Chadigarh	6,000	1,000	10
28.	Delhi	36,300	32,000	320
29.	Pondicherry	4,500	3,400	34
30.	Lakshadweep	300	—	—
31.	Dadar & Nager Haveli	—	—	—
32.	Daman & Diu	—	—	—
		11,73,350	2,36,700	2,971

आलू की पैदावार बढ़ाना

749. **प्रो॰ राम लखन सिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष खाद बीज एवं आधुनिक उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) भारत सरकार किसानों को फसलों के उत्पादन के लिए जिसमें आलू भी शामिल है, नियंत्रण से मुक्त उर्वरकों की बिक्री पर म्यूरिएट आफ पोटाश तथा देशी डाई अमोनियम फासफेट पर, प्रत्येक पर प्रति टन 1000/-रुपए, सिंगल सुपर फासफेट पर प्रतिटन 340/- रुपए तथा देशी मिश्र उर्वरकों पर प्रति टन 435-999 रुपए (ग्रेड पर निर्भर करते हुए) की रियायत दे रही है। आलू सहित कन्दमूल फसलों के विकास की स्कीम के अंतर्गत उत्पादन लागत को कम करने तथा उत्पादकता को सुधारने के लिए ट्यूबर सीडस के स्थान पर टू पोटेटो सीड के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सहयता दी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत उत्पादित बीज मिनीकिट्स के माध्यम से रियायती दरों पर किसानों में वितरित किये जाते हैं। तथापि, इस समय आलू उत्पादन के लिए रियायती दरों पर आधुनिक उपकरण प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है।

उत्तर प्रदेश में यूरिया की आवश्यकता

750. **श्री संघ प्रिय गौतम:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला-वार यूरिया की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता थी;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य को यूरिया की अनुमानतः कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी; और

(ग) सरकार इस मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में यूरिया की जिले-वार खपत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) यूरिया की आवश्यकता का निर्धारण प्रत्येक फसल मौसम जैसे खरीफ (अप्रैल-सितम्बर) और रबी (अक्तूबर-मार्च) से पहले राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के परामर्श से किया जाता है। खरीफ, 1995 मौसम हेतु उत्तर प्रदेश में यूरिया की आवश्यकता 18.40 लाख मीटरी टन आंकी गई है। रबी, 1995-96 के लिए यूरिया का निर्धारण उपरोक्त पद्धति के अनुसार उचित समय पर किया जाएगा।

(ग) यूरिया की मांग स्वदेशी उत्पादन तथा आयात माध्यम से पूरी की जाती है।